



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 760]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2006/आषाढ़ 28, 1928

No. 760]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 2006/ASADHA 28, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2006

(आयकर)

का.आ. 1136(अ).—जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा जापान सरकार के बीच अभिसमय को संशोधित करने वाला अनुबद्ध प्रोटोकॉल उक्त प्रोटोकॉल के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए अभिसमय को संशोधित करने वाले प्रोटोकॉल के अनुच्छेद V के पैराग्राफ 1 के अनुसार 28 जून, 2006 को प्रवृत्त होगा;

इसलिए, अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा जापान सरकार के बीच अभिसमय को संशोधित करने वाले उक्त प्रोटोकॉल के सभी प्रावधानों को दिनांक 28 जून, 2006 से भारत संघ में प्रवृत्त किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 186/2006/फा. सं. 506/69/81-एफ टी डी-1]

डी. पी. सेन गुप्ता, संयुक्त सचिव

अनुबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और जापान सरकार के बीच अभिसमय को संशोधित करने वाला प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार और जापान सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और

जापान सरकार के बीच दिनांक 7 मार्च, 1989 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित अभिसमय को संशोधित करने के इरादे से हैं (इसके बाद “उक्त अभिसमय” के रूप में संदर्भित), में निम्नलिखित बातों पर सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद I

अभिसमय के अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 2 को विलोपित किया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश को संदत्त करने वाली कम्पनी एक निवासी है लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितग्राही स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांशों की सकल धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस पैराग्राफ के उपबंध उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेंगे जिन लाभों में से लाभांश अदा किए जाते हैं।

अनुच्छेद II

अभिसमय के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2 को विलोपित किया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“2. तथापि, ऐसे ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसमें यह उद्भूत होता है लेकिन यदि प्राप्तकर्ता ऐसे ब्याज का हितग्राही स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।”

अनुच्छेद III

अभिसमय के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2 को विलोपित किया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“2. तथापि, ऐसी रॉयल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार भी कर लगाया जा सकेगा, लेकिन जिनमें ये उद्भूत होते हैं किन्तु यदि प्राप्तकर्ता रॉयल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों का हितग्राही स्वामी है तो इस प्रकार प्रभावित कर रॉयल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों की सकल धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।”

अनुच्छेद IV

अभिसमय के अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (ग) को विलोपित किया जाएगा।

अनुच्छेद V

1. यह प्रोटोकॉल प्रत्येक संविदाकारी राज्य की कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन को दर्शाने वाली राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान की तारीख के उपरान्त तीसवें दिन को प्रवृत्त होगा।

2. यह प्रोटोकॉल लागू होगा :

(क) जापान में :

(i) स्रोत पर रोके गए करों के सम्बन्ध में :

(कक) उस कैलेंडर वर्ष जिसमें उक्त प्रोटोकॉल प्रवृत्त हुआ है, की प्रथम जुलाई को अथवा उसके बाद कराधेय धनराशि के लिए, यदि प्रोटोकॉल किसी कैलेंडर वर्ष की प्रथम जुलाई के पूर्व प्रवृत्त हुआ हो;

अथवा

(खख) उस कैलेंडर वर्ष के अगले अनुवर्ती वर्ष जिसमें उक्त प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है, की प्रथम जनवरी को अथवा उसके बाद कराधेय धनराशि के लिए, यदि उक्त प्रोटोकॉल किसी कैलेंडर वर्ष के 30 जून के उपरान्त प्रवृत्त होता है; और

(ii) आय पर कर जो स्रोत पर नहीं रोका गया हो, के सम्बन्ध में, उस कैलेंडर वर्ष के अगले अनुवर्ती वर्ष जिसमें उक्त प्रोटोकॉल प्रवृत्त हुआ हो, की प्रथम जनवरी को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कराधेय वर्ष की आय के सम्बन्ध में; और

(ख) भारत में :

(i) स्रोत पर रोके गए करों के सम्बन्ध में, उस कैलेंडर वर्ष के अगले अनुवर्ती वर्ष जिसमें उक्त प्रोटोकॉल प्रवृत्त हो, की प्रथम अप्रैल को अथवा उसके बाद संदत्त अथवा क्रेडिट की गई धनराशि के सम्बन्ध में,

और

(ii) उस कैलेंडर वर्ष के अगले अनुवर्ती वर्ष जिसमें उक्त प्रोटोकॉल प्रवृत्त हुआ हो, के प्रथम अप्रैल को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए आय पर करों के संबंध में।

3. यह प्रोटोकॉल अभिसमय के प्रवृत्त रहने तक प्रभावी रहेगा।

उनकी सम्बद्ध सरकारों द्वारा उनके लिए विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरी के साक्ष्य में यह प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित किया गया है।

यह टोक्यो में आज दिनांक 24 फरवरी, 2006 को हिन्दी, जापानी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पादित किया गया है, इनमें से प्रत्येक पाठ समान रूप से प्रामाणिक है। व्याख्याओं में किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की

जापान सरकार

सरकार की ओर से

की ओर से

ह./-

ह./-

(एम. एल. त्रिपाठी)

(तारो आसो)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2006

(INCOME-TAX)

S.O. 1136(E).—Whereas the annexed Protocol amending the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income shall enter into force on the 28th day of June, 2006 in accordance with paragraph 1 of Article V of the Protocol amending the Convention for giving effect to the provisions of the said Protocol;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Protocol amending the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income shall be given effect to in the Union of India with effect from the 28th day of June, 2006.

[Notification No. 186/2006/F.No. 506/69/81-FTD-I]

D.P. SENGUPTA, Jt. Secy.

ANNEXURE

Protocol Amending the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income

The Government of the Republic of India and the Government of Japan,

Desiring to amend the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed at New Delhi on 7th March, 1989 (hereinafter referred to as "the Convention"),

Have agreed as follows :

ARTICLE I

Paragraph 2 of Article 10 of the Convention shall be deleted and replaced by the following :

"2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid."

ARTICLE II

Paragraph 2 of Article 11 of the Convention shall be deleted and replaced by the following :

“2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of the Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.”

ARTICLE III

Paragraph 2 of Article 12 of the Convention shall be deleted and replaced by the following :

“2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.”

ARTICLE IV

Sub-paragraph (c) of paragraph 3 of Article 23 of the Convention shall be deleted.

ARTICLE V

1. This Protocol shall be approved in accordance with the legal procedures of each of the Contracting States and shall enter into force on the thirtieth day after the date of exchange of diplomatic notes indicating such approval.
2. This Protocol shall be applicable :
 - (a) in Japan :
 - (i) with respect to taxes withheld at source :
 - (aa) for amounts taxable on or after 1st July of the calendar year in which the Protocol enters into force, if the Protocol enters into force before 1st July of a calendar year;
 - or
 - (bb) for amounts taxable on or after 1st January of the calendar year next following the year in which the Protocol enters into force, if the Protocol enters into force after 30th June of a calendar year; and
 - (ii) with respect to taxes on income which are not withheld at source, as regards income for any taxable year beginning on or after 1st January of the calendar year next following that in which the Protocol enters into force; and
 - (b) in India :
 - (i) with respect to taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after 1st April of the calendar year next following that in which the Protocol enters into force;
 - and
 - (ii) with respect to taxes on income for any previous year beginning on or after 1st April of the calendar year next following that in which the Protocol enters into force.

3. This Protocol shall remain in effect as long as the Convention remains in force.

In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Tokyo on this 24th day of February, 2006 in the Hindi, Japanese and English languages, each text being equally authentic. In case of any divergence of interpretations, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of India :

For the Government of Japan :

Sd./-
(M. L. TRIPATHI)

Sd./-
(TARO ASO)